

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2034]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2016/श्रावण 25, 1938

No. 2034]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2016/SRAVANA 25, 1938

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली. 11 अगस्त. 2016

का.आ. 2713(अ).— संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद् ने अपनी 5297वीं बैठक में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अधीन संकल्प 1636 (2005) [इस आदेश में उपाबंध 1 के रूप में संलग्न] को अंगीकार किया है जिसके अनुसार सभी राष्ट्रों को लेबनान सरकार अथवा समिति द्वारा यथाविनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अपने राज्यक्षेत्रों में प्रवेश करने अथवा उनके पारगमन को रोकने के आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता होगी तथा संकल्प के पैराग्राफ 3 (क) के अनुसार सभी राष्ट्र अपने प्रदेशों में ऐसी सभी निधियों, वित्तीय आस्तियों तथा आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाएं, जो ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किए जा रहे हों अथवा उनके स्वामित्व में हों; अथवा ऐसे निकायों के स्वामित्व में हो जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण या स्वामित्व ऐसे व्यक्तियों या उनकी ओर से या उनके निदेश के अनुसार काम करने वालों के हाथ में हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके नागरिकों या उनके राज्यक्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा संकल्प 1595(2005) द्वारा या लेबनान सरकार द्वारा स्थापित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या निकायों के लाभार्थ उपलब्ध न कराया जाए।

और जबिक संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के संकल्प 1748 (2007) के अनुसार सदस्य राष्ट्रों के लिए संकल्प 1595 (2005), 1636 (2005), 1644 (2005), 1686 (2006), 1748 (2007) में अंतर्विष्ट प्रावधानों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना आवश्यक है।

और जबिक केन्द्रीय सरकार लेबनान की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अधीन अंगीकृत सुरक्षा परिषद् के उक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम 1947 (1947 का 43) के अधीन एक आदेश जारी करना आवश्यक और समीचीन समझती है।

4029 GI/2016 (1)

अत: अब संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थातु:-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्पों के कार्यान्वयन संबंधी लेबनान आदेश, 2016 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएं:- (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "संकल्प" से 31 अक्तूबर 2005 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के संकल्प 1636 (2005) अभिप्रेत है और इसमें संकल्प 1595 (2005), 1644 (2005), 1686 (2006), 1748 (2007) है;
 - (ख) "उपाबंध" से; इस आदेश से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है।
 - (ग) "समिति" से संकल्प 1636 (2005) के पैराग्राफ 3 (ख) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है।
 - (घ) "आयोग" से संकल्प 1595 (2005) के पैराग्राफ 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् द्वारा स्थापित आयोग अभिप्रेत है।
 - (2) उन शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं और तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो अन्य विधियों में क्रमश: उनके हैं।
- 3. व्यक्तियों और निकायों पर आदेश का लागू होना:- इस आदेश के उपाबंध, जैसा कि समय-समय पर संशोधित होते हैं, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और निकायों पर लागू होंगे। व्यक्ति तथा निकाय से आयोग अथवा आयोग के साथ करार में लेबनान सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तथा समिति द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और उनकी वेबसाइट पर आपतित एवं विनिर्दिष्ट व्यक्तियों तथा सत्ताएं अभिप्रेत है।
- **4. संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार की शक्तियां**:- केन्द्रीय सरकार के पास निम्नलिखित आवश्यक उपाय करने की सभी शक्तियां होंगी,

यात्रा पाबंदी

(1) आयोग अथवा लेबनान सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को भारत की सीमा में प्रवेश करने अथवा पारगमन से रोकना, परंतु इस पैराग्राफ में उल्लिखित कोई बात भारत सरकार को अपने स्वयं के नागरिकों को अपनी सीमा में प्रवेश करने से इंकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगी।

परंतु यह निम्नलिखित को लागू नहीं होगा:

- (i) जहां समिति यह अवधारित करे कि ऐसी यात्रा धार्मिक दायित्वों सहित मानवीय आवश्यकता के आधार पर उचित है [संदर्भ संकल्प 1636 (2005) के उपाबद्ध के पैराग्राफ 2 (i) पर उपाबद्ध];
- (ii) जहां समिति यह तय करे कि कोई छूट संकल्प 1636 (2005) के उद्देश्यों को अन्यथा आगे बढ़ाएगी [संदर्भ संकल्प 1636 (2005) के उपाबद्ध पैराग्राफ 2 (i) पर उपाबद्ध];

आस्तियों पर रोक लगाना

(2) (क) सभी उन निधियों, वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाना जो भारत में स्थित हैं, जो कमीशन या लेबनान सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में हैं या ऐसे व्यक्तियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में हैं जो उनकी ओर से या उनके निर्देश पर काम कर रहें हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कमीशन या लेबनान सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को भारतीय नागरिकों द्वारा या भारतीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कोई भी निधि, वित्तीय आस्ति और आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाने पर रोक लगायी जाए:

परन्तु यह उन निधियों या आर्थिक उपायों पर लागू नहीं होगा जो खाद्य पदार्थों, िकराया या बंधक, दवाओं और चिकित्सा उपचार, करों, बीमा प्रीमियम, और सार्वजनिक उपयोगिता प्रभार के लिए भुगतान सिहत बुनियादी खर्चों के रूप में या विशेषतः यथोचित पेशेवरों को शुल्क के भुगतान और विधिक सेवाओं के प्रावधानों से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति या रोकी गई निधियों या अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों को रखने या उनके अनुरक्षण के संबंध में किए गए दिए गए शुल्क या सेवा प्रभार के लिए आवश्यक हैं [संदर्भ संकल्प 1636 (2005) के पैरा 2 (ii) पर उपाबद्ध];

उपाबंध

[पैराग्राफ 2(ख) देखें]

संकल्प 1636 (2005)

31 अक्टूबर 2005 को 5297वीं बैठक में सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत किया गया

सुरक्षा परिषद,

अपने सभी पिछले संकल्पों, विशेष रूप से 7 अप्रैल 2005 के 1595 (2005), 28 सितम्बर 2001 के 1373 (2001) और 8 अक्टूबर 2004 के 1566 (2004) संकल्पों की पृष्टि करती है,

लेबनान की सरकार के एकमात्र और अनन्य अधिकार के अधीन लेबनान की संप्रभुता , क्षेत्रीय अखंडता, एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में अपनी माँग को दोहराते हुए पुनः पुष्टि करती है,

पुनः पृष्टि करती है कि अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है।

अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र जांच कमीशन (एस/2005/662) ("कमीशन") की रिपोर्ट सावधानीपूर्वक देख लेने के बाद 14 फरवरी 2005 के बेरूत, लेबनान में आतंकवादी बम विस्फोट, जिसमें पूर्व लेबनानी प्रधानमंत्री राफ़ीक़ हरीरी और 22 अन्य मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए थे, की जांच के विषय में,

कमीशन द्वारा किए गए श्रेष्ठ पेशेवर कार्य की प्रशंसा करते हुए जो इसने कठिन परिस्थितियों में लेबानानी प्राधिकारियों को इस आतंकवादी कार्य के सभी पक्षों में जाँच में सहायता दे कर पूरा किया है और कमीशन के इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि जाँच अभी पूरी नहीं हुई है,

उन देशों की प्रशंसा करते हुए जिन्होंने कमीशन को अपने कर्तव्य निभाने में मदद दी है, संकल्प 1595 के अनुच्छेद 3 (2005) के अनुसार लेबानानी प्राधिकारियों द्वारा कमीशन को अपने कर्तव्य निभाने में दिए गए पूर्ण सहयोग की प्रशंसा भी करती है,

यह स्मरण करते हुए कि इसके प्रासंगिक संकल्पों के अनुसार, सभी देशों से अपेक्षित है कि वे आपराधिक जांच या आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही के संबंध में एक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाएं और विशेष रूप से स्मरण कराते हुए कि यह अनुरोध इसके संकल्प 1595 (2005) में किया गया है कि सभी देश और सभी पक्ष कमीशन के साथ पूरा सहयोग करें,

कमीशन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि जाँच में काफी प्रगति पहले ही की जा चुकी है और इसने पर्याप्त परिणाम प्राप्त कर लिए हैं, यह अत्यंत महत्व का होगा कि पूरी तरह से इस आतंकवादी कार्रवाई के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने हेतु और विशेष रूप से उनकी पहचान करने के लिए और इसकी योजना, प्रयोजन, संयोजन और अपराध कार्य में उन सभी की जवाबदेही तय करने के लिए लेबनान में और उसके बाहर दोनों स्थानों पर ट्रायल जारी रखा जाए।

लेबनान के लोगों की मांग के प्रति जागरूक रहते हुए कि जो लोग उस आतंकवादी बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें पूर्व लेबनानी प्रधानमंत्री राफ़ीक़ हरीरी और अन्य की मौत हो गई, की पहचान की जाए और जवाबदेही तय की जाए,

इस बारे में लेबनान के प्रधानमंत्री द्वारा सेक्नेटरी – जनरल को लिखे गए 13 अक्तूबर 2005 (एस/2005/651) के पत्र की पावती देते हुए अनुरोध किया गया कि कमीशन के अधिदेश को बढ़ाया जाए जिससे आतंकवादी अपराध के विभिन्न आयामों में से, किसी की भी, कमीशन आगे की जांच पड़ताल में सक्षम लेबनान की अधिकारियों की सहायता जारी रख सके।

यह भी कि कमीशन की समवर्ती सिफारिश को स्वीकार करते हुए कि इस आतंकवादी कार्रवाई की ठीक तह तक पहुँच कर मदद करने के लिए लेबनान के अधिकारियों की अंतरराष्ट्रीय सहायता पूरी तरह जारी रखने की जरूरत है और यह कि सुरक्षा और न्याय के क्षेत्र में लेबनान के अधिकारियों हेतु एक सहायता और सहयोग मंच की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से एक निरंतर प्रयास आवश्यक है,

सत्य की खोज में लेबनान की सहायता जारी रखने के लिए और इस आतंकवादी कार्रवाई में उन लोगों की अपने अपराध के लिए जवाबदेही तय करने के लिए तैयार हैं,

सभी देशों से अपील की जाती है कि लेबानानी अधिकारियों को और कमीशन को वह सब सहायता दें जिसकी उन्हें जाँच में जरुरत है और विशेष रूप से उन्हें वह सब प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराएं जो इस आतंकवादी हमले से संबंधित हो सकती है.

राष्ट्रीय एकता और लेबनान की स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि दोहराते हुए, इस पर बल देती है कि भविष्य के लेबनान के बारे में स्वयं लेबनानियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से, जो धमकी और विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त हो, निर्णय लिया जाए और इस संबंध कि लेबनान की स्थिरता को कमजोर करने का प्रयास में किसी चेतावनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कमीशन के निष्कर्ष को ध्यान में रखते कि सीरिया द्वारा लेबनान के संस्थानों और सामाजिक जीवन में घुसपैठ करने और और लेबनान की खुफिया सेवाओं के साथ मिलकर काम करने को देखते हुए उस परिदृश्य की कल्पना करना मुश्किल होगा जहाँ इस तरह की एक जटिल हत्या की साजिश को, उनकी जानकारी के बिना अंजाम दे दिया जाए और इस पर विश्वास करने के लिए संभावित कारण यह है कि सीरियाई सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों के अनुमोदन के बिना पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या करने का निर्णय लिया ही नहीं जा सकता था।

कमीशन के निष्कर्ष के प्रति जागरूक रहते हुए कि जबिक सीरियाई अधिकारियों ने, प्रारंभिक हिचकिचाहट के बाद, आयोग के साथ एक सीमित मात्रा में सहयोग किया है, कई सीरियाई अधिकारियों ने झूठा या गलत बयान देकर जांच को गुमराह करने की कोशिश की है,

दृढ़ मत है कि यह सिद्धांत रूप में अस्वीकार्य है कि आतंकवाद के कार्य के लिए किसी को भी कहीं भी किसी भी कारण से, जांच में अपनी ही रुकावट के कारण या नेकनियती के साथ सहयोग करने में विफलता के कारण सहित, जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए,

निर्धारित करते हुए कि यह आतंकवादी कार्य और इसके निहितार्थ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं,

इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के महत्व और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अधीन कार्यवाही करते हुए,

- I -

- 1) कमीशन की रिपोर्ट का स्वागत करती है;
- 2) आयोग के निष्कर्ष को चरम चिंता के साथ नोट करती है कि इस आतंकवादी कार्रवाई में सबूत लेबनानी और सीरियाई दोनों ओर के अधिकारियों की भागीदारी पर इशारा कर रहे हैं और ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना मुश्किल है जहाँ इस तरह की एक जटिल हत्या की साजिश को उनकी जानकारी के बिना अंजाम दे दिया जाए;

- 3) इस अपराध की जांच में सहायता करने के लिए एक कदम के रूप में और अपराध या किसी भी व्यक्ति की मासूमियत के अंतिम न्यायिक दृढ़ संकल्प पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्णय लेती है;
 - क) कि आयोग या लेबनान की सरकार द्वारा संदिग्ध के रूप में निर्दिष्ट सभी व्यक्ति जो इस आतंकवादी घटना की योजना, प्रायोजन, संयोजन और अपराध कार्य में शामिल हैं, इस प्रकार निर्दिष्ट किए जाने पर और उप अनुच्छेद (ख) में निम्नलिखित अनुसार गठित समिति की सहमित के अनुसार, निम्नलिखित कार्यवाहियों के अधीन होंगे:
 - सभी देश ऐसे व्यक्तियों का अपने क्षेत्रों के माध्यम से प्रवेश या पारगमन को रोकने के लिए सभी उपाय करेंगे, तथापि इस पैराग्राफ में दी गई कोई भी बात एक देश को अपने स्वयं के नागरिकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु प्रतिषेध नहीं करती है, या, यदि ऐसे कोई नागरिक उनके क्षेत्र में पाए जाते हैं तो सुनिश्चित करेंगे कि अनुरोध किए जाने पर, लागू क़ानून के अनुसार वे कमीशन द्वारा साक्षात्कार के लिए उपलब्ध रहें;
 - सभी देश उन सभी निधियों, वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाएंगे जो उनके क्षेत्रों में हैं, जो ऐसे व्यक्तियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में हैं या जो ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाओं द्वारा धारित हैं या ऐसे व्यक्तियों के से स्वामित्व या नियंत्रण में हैं जो उनकी ओर से या उनके निर्देश पर काम कर रहे हैं; यह सुनिश्चित करना कि ऐसे किसी भी उन व्यक्तियों या संस्थाओं को उनके नागरिकों द्वारा या उनके क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा या उनके लाभ के लिए कोई निधियाँ, वित्तीय आस्तियाँ या आर्थिक संसाधन उपलब्ध न कराए जाएं; और किसी ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यक्तियों, जो उनकी ओर से काम कर रहे हैं, की संपत्ति या वित्तीय लेनदेन पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय जांच पर, लागू कानून के अनुसार वित्तीय जानकारी साझा करने सहित पूरी तरह से सहयोग करना;
 - ख) प्रक्रिया के अपने अनंतिम नियमों में नियम 28 के अनुसार, सुरक्षा परिषद की एक समिति का गठन करना जिसमें परिषद के सभी सदस्य, इस संकल्प के अनुलग्नक में वर्णित कार्यों को शुरू करने के लिए, शामिल होंगे:
 - ग) कि समिति और अन्य कोई कार्यवाही जो अभी उप अनुच्छेद (क) के अधीन चल रही है, समिति द्वारा सुरक्षा परिषद को यह रिपोर्ट किए जाने पर कि इस आतंकवादी हमले से संबंधित सभी जांच और न्यायिक कार्यवाही पूरी हो चुकी हैं, जब तक अन्यथा रूप से सुरक्षा परिषद द्वारा निर्णय न लिया जाए, बंद हो जाएगी;
- 4) निर्धारित करती है कि इस आतंकवादी कार्रवाई में किसी भी देश की भागीदारी, विशेष रूप से संकल्पों 1373 (2001) और 1566 (2004) के अनुसार, आतंकवाद रोकने के लिए काम करने और इसका समर्थन करने से परहेज करने के दायित्वों का उस देश द्वारा उल्लंघन किए जाने का कारण होगी और यह कि यह लेबनान की संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने के बारे में यह अपने दायित्व का गंभीर उल्लंघन करने के समान होगा;
- 5) आयोग के निष्कर्ष को चरम चिंता के साथ नोट करती है कि जबिक सीरियाई अधिकारियों ने कमीशन के साथ दिखावटी रूप से, वास्तविकता में नहीं, सहयोग किया है, कई सीरियाई अधिकारियों ने झूठा या गलत बयान देकर जांच को गुमराह करने की कोशिश की है, और निर्धारित करती है कि जाँच में सीरिया द्वारा लगातार किया जा रहा असहयोग संबंधित संकल्पों, 1373 (2001), 1566 (2004) और 1595 (2005) सहित, प्रासंगिक प्रस्तावों के तहत उनके दायित्वों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा:

6) आयोग के साथ सहयोग करने के लिए अब अपने इरादे के बारे में सीरिया द्वारा हाल ही दिए गए बयान को कि वह कमीशन के साथ सहयोग करेगा, नोट करती है और सीरिया की सरकार से उम्मीद करती है कि अब किए गए सभी वादों को पूर्ण प्रतिबद्धताओं के साथ लागू करे;

- II -

- 7) स्वीकार करती है कि, सेक्रेटरी-जनरल को लिखे गए 13 अक्टूबर 2005 के अपने पत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार और कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई संस्तुति के अनुसार, पूरी तरह से इस जघन्य अपराध के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए आयोग की ओर से लेबनान को सहायता जारी रखना आवश्यक हो जाता है; उन सभी की, साथ ही सहअपराधियों की, जो इसकी योजना, प्रयोजन, संयोजन और आतंकवादी कार्य में शामिल थे, पहचान की जानी चाहिए और दण्ड दिया जाना चाहिए;
- 8) इस बारे में सेक्नेटरी-जनरल के निर्णय का स्वागत करती है कि उनके संकल्प 1595 (2005) में सुरक्षा परिषद द्वारा यथा अधिकृत, कमीशन का अधिदेश 15 दिसम्बर 2005 तक बढ़ाया जाए, और निर्णय लेती है कि लेबनानी सरकार द्वारा अनुरोध किया जाने और कमीशन द्वारा संस्तुत किया जाने पर यह अधिदेश आगे बढ़ाएगी;
- 9) लेबनानी अधिकारियों की प्रशंसा करती है कि उन्होंने जाँच के संबंध में, आयोग की सिफारिश सहित, विशेष रूप से उन पूर्व लेबनानी सुरक्षा अधिकारियों की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने के लिए, जिनके इस आतंकवादी कार्य में शामिल होने शामिल होने का संदेह था, एक साहसी निर्णय लिया और लेबनानी अधिकारियों को प्रोत्साहित करती है कि वे इसी पक्के इरादे के साथ अपने प्रयासों को जारी रखें जिससे अपराध की ठीक तह तक पहुँचा जा सके।

- III -

- 10) आयोग के निष्कर्ष का समर्थन करती है कि सीरियाई अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है कि वे प्रश्नों के उस बड़े भाग को स्पष्ट करें जो अभी अनसुलझा रह गया है;
- 11) इस संदर्भ में निर्णय लेती है कि:
- (क) सीरिया द्वारा उन सीरियाई अधिकारियों को या व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिन्हें कमीशन आतंकवादी कार्य की योजना, प्रायोजन, संयोजन और अपराध कार्य में संदिग्ध के रूप में शामिल मानता है और उन्हें पूरी तरह से कमीशन को उपलब्ध करना चाहिए;
- (ख) कमीशन को सीरिया के संदर्भ में वही अधिकार और प्राधिकार होंगे जैसे संकल्प 1595 (2005) के अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं और सीरिया को कमीशन के साथ पूर्ण रूप से और बिना किसी शर्त के आधार पर सहयोग करना चाहिए;
- (ग) कमीशन को इस जाँच से जुड़े सीरियाई अधिकारियों और व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने के लिए स्थान और तौर-तरीके निर्धारित करने का अधिकार होगा;
- 12) आग्रह करती है कि सीरिया, या तो सीधे या परोक्ष रूप से, लेबनान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेबनान को अस्थिर करने के उद्देश्य से किसी भी प्रयास से बचेगा और इस देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेगा;

- IV -

13) कमीशन से अनुरोध करती है कि वह जाँच में हुई प्रगति पर अपनी रिपोर्ट, आयोग द्वारा सीरियाई अधिकारियों से प्राप्त किए गए सहयोग सिहत, 15 दिसम्बर 2005 तक या यदि कमीशन समझता है कि ऐसा सहयोग संकल्प की आवश्यकता पूरी नहीं कर रहा है तो कभी भी उस समय से पूर्व सौंप दे, जिससे परिषद, यदि आवश्यक हो तो, आगे की कार्रवाई पर विचार कर सके;

- 14) लेबनानी सरकार की ओर से सहायता के लिए किसी भी अतिरिक्त अनुरोध पर विचार करने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त करती है जिससे उन सभी लोगों की इस अपराध के प्रति जवाबदेही तय की जा सके:
- 15) मामले पर पुनर्विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

उपाबद्ध

इस संकल्प के अनुच्छेद 3 के अनुसार गठित की गई समिति के कार्य निम्नलिखित अनुसार हैं:

- 1. इस संकल्प के अनुच्छेद 3 (क) में दी गई कार्यवाही के अधीन कमीशन या लेबनानी सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को पंजीकृत करना, बशर्ते कि ऐसे पदनाम की प्राप्ति पर दो दिन के भीतर समिति के किसी सदस्य की ओर से आपत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, उस स्थिति में अनुच्छेद 3 (क) में दी गई कार्यवाही की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए समिति की बैठक पंद्रह दिन की समय सीमा में होगी।
- 2. प्रत्येक मामले के अनुसार अनुच्छेद 3 (क) में दी गई कार्यवाही के अपवादों को अनुमोदित करना:
- (i) यात्रा प्रतिबंध के संबंध में, जहां समिति निर्धारित करती है कि ऐसी यात्रा धार्मिक दायित्व सहित मानवीय आवश्यकता के आधार पर जायज़ है या जहां समिति निर्धारित करती है कि छूट इस संकल्प के उद्देश्यों को अन्यथा रूप से आगे बढ़ाएगी;
- (ii) निधियों और अन्य आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने के बारे में, जहां समिति निर्धारित करती है कि खाद्य पदार्थों, किराया या बंधक, दवाओं और चिकित्सा उपचार, करों, बीमा प्रीमियम, और सार्वजनिक उपयोगिता प्रभार के लिए भुगतान सहित बुनियादी खर्चों के रूप में या विशेषतः यथोचित पेशेवरों को शुल्क के भुगतान और क़ानूनी सेवाओं के प्रावधानों से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति या रोकी गई निधियों या अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों को रखने या उनके अनुरक्षण के संबंध में किए गए दिए गए शुल्क या सेवा प्रभार सहित ऐसे अपवाद बुनियादी खर्चों के लिए आवश्यक हैं:
- 3. कमीशन या लेबनानी सरकार की अधिसूचना पर अनुच्छेद 3 (क) में दी गई कार्यवाही से किसी व्यक्ति को हटाने को पंजीकृत करना कि व्यक्ति अब इस आतंकवादी कार्रवाई में शामिल होने के संदेह में नहीं है, बशर्ते कि ऐसे पदनाम की प्राप्ति पर दो दिन के भीतर समिति के किसी सदस्य की ओर से आपत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, उस स्थिति में अनुच्छेद 3 (क) में दिए गए उपायों की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए समिति की बैठक पंद्रह दिन की समय सीमा में होगी।
- 4. उन सभी सदस्य देशों को सूचित करने हेत् जिनके लोग अनुच्छेद 3 (क) के कार्यवाही के अधीन हैं।

[फा. सं. यू.-II/152/31/2015]

रूदेन्द्र टंडन, संयुक्त सचिव (यूएनपी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 11th August, 2016

S.O. 2713(E).— Whereas, the Security Council of the United Nations in its 5297th Meeting adopted Resolution 1636 (2005) [appended to this Order as Annexure 1] under Chapter VII of the Charter of the United Nations which required all States to take necessary measures to prevent entry into or transit through their territories of individuals as designated by the Committee or Government of Lebanon and paragraph 3(a) of the resolution required all States to freeze all funds, financial assets and economic resources that are on their territories that are owned or controlled, directly or indirectly, by such individuals, or that are held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by such individuals or by persons acting on their behalf or at their direction and to ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by their nationals or by any persons within their territories to or for the benefit of such individuals or entities designated by the Commission established by the resolution 1595(2005) or by the Government of Lebanon.;

And whereas, Resolution 1748 (2007) of the Security Council of the United Nations requires Member States to fully implement the provisions contained in Resolutions 1595(2005), 1636(2005), 1644(2005), 1686(2006), 1748(2007);

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolutions of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations to protect the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Lebanon;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to give effect to the said Resolutions, namely:-

- **1. Short title and commencement . -** (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Lebanon Order, 2016.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions** . **-** (1) In this Order, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Resolution" means the Resolution 1636(2005), of the Security Council of the United Nations adopted on 31st October, 2005 and includes Resolutions 1595(2005), 1644(2005), 1686(2006), 1748(2007);
 - (b) "Annexure" means the Annexure appended to this Order;
- (c) "Committee" means the Committee established by the Security Council of the United Nations in accordance with paragraph 3(b) of the Resolution 1636(2005);
- (d) "Commission" means the Commission established by the Security Council of the United Nations in accordance with paragraph 1 of Resolution 1595(2005).
- (2) Words and expressions used but not defined in this Order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.
- **3. Application of Order to individuals and entities .-** The provisions of this Order, as amended from time to time, apply to designated individuals and entities. The term individuals and entities means individuals and entities as designated by the Commission or Government of Lebanon in agreement with the Commission and notified by the Committee from time to time and updated and specified on their website.
- **4. Powers of the Central Government to give effect to the Resolution .-** The Central Government shall have all the powers to take necessary measures to,

Travel Ban

(1) Prevent the entry into or transit through the territory of India of individuals designated by the Commission or Government of Lebanon provided that nothing in this paragraph shall oblige Government of India to refuse its own nationals entry into its territory:

Provided that it shall not apply:

- (i) where the Committee determines that such travel is justified on the ground of humanitarian need, including religious obligation [Reference paragraph 2(i) of annex of resolution 1636(2005)];
- (ii) where the Committee concludes that an exemption would otherwise further the objectives of resolution 1636(2005) [Reference paragraph 2(i) of annex of resolution 1636(2005)];

Asset Freeze

(2) (a) freeze all funds, financial assets and economic resources located in India that are owned or controlled, directly or indirectly, by individuals or entities designated by the Commission or the Government of Lebanon, or owned or controlled, directly or indirectly, by individuals or by persons acting on their behalf or at their direction;

(b) ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by Indian nationals or by any individuals or entities within territory of India, to or for the benefit of the individuals or entities designated by the Commission or the Government of Lebanon:

Provided that it shall not apply to funds and other economic measures that have been determined by the Committee, to be necessary for basic expenses, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or other financial assets or economic resources [Reference paragraph 2(ii) of annex of resolution 1636(2005)].

Annexure

[See paragraph 2(b)] Resolution 1636 (2005)

Adopted by the Security Council at its 5297th meeting, on

31 October 2005

The Security Council,

Reaffirming all its previous relevant resolutions, in particular resolutions 1595 (2005) of 7 April 2005, 1373 (2001) of 28 September 2001, and 1566 (2004) of 8 October 2004,

Reiterating its call for the strict respect of the sovereignty, territorial integrity, unity and political independence of Lebanon under the sole and exclusive authority of the Government of Lebanon,

Reaffirming that terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to peace and security,

Having examined carefully the report of the international independent investigation Commission (S/2005/662) ("the Commission") concerning its investigation into the 14 February 2005 terrorist bombing in Beirut, Lebanon, that killed former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others, and caused injury to dozens of people,

Commending the Commission for the outstanding professional work it has accomplished under difficult circumstances in assisting the Lebanese authorities in their investigation of all aspects of this terrorist act, and taking note of the Commission's conclusion that the investigation is not yet complete,

Commending States which have provided assistance to the Commission in the discharge of its duties, commending also the Lebanese authorities for the full cooperation they have provided to the Commission in the discharge of its duties, in accordance with paragraph 3 of resolution 1595 (2005),

Recalling that pursuant to its relevant resolutions, all States are required to afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal proceedings relating to terrorist acts, and recalling in particular that it had requested in its resolution 1595 (2005) all States and all parties to cooperate fully with the Commission,

Taking note of the Commission's findings that although the inquiry has already made considerable progress and achieved significant results, it is of the utmost importance to continue the trail both within and outside Lebanon in order to elucidate fully all aspects of this terrorist act, and in particular to identify and hold accountable all those who bear responsibility in its planning, sponsoring, organization and perpetration,

Mindful of the demand of the Lebanese people that all those responsible for the terrorist bombing that killed former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and others be identified and held accountable,

Acknowledging in this connection the letter of the Prime Minister of Lebanon to the Secretary-General of 13 October 2005 (S/2005/651) requesting that the mandate of the Commission be extended to enable the Commission to continue to assist the competent Lebanese authorities inany further investigation of the various dimensions of the terrorist crime,

Acknowledging also the concurrent recommendation of the Commission that continued international assistance is needed to help the Lebanese authorities get right to the bottom of this terrorist act, and that a sustained effort on the part of the international community to establish an assistance and cooperation platform together with the Lebanese authorities in the field of security and justice is essential,

Willing to continue to assist Lebanon in the search for the truth and in holding those responsible for this terrorist act accountable for their crime.

Calling upon all States to extend to the Lebanese authorities and to the Commission the assistance they may need and request in connection with the inquiry, and in particular to provide them with all relevant information they may possess pertaining to this terrorist attack,

Reaffirming its profound commitment to the national unity and stability of Lebanon, emphasizing that the future of Lebanon should be decided through peaceful means by the Lebanese themselves, free of intimidation and foreign interference, and warning in this regard that attempts to undermine the stability of Lebanon will not be tolerated,

Taking note of the Commission's conclusions that, given the infiltration of Lebanese institutions and society by the Syrian and Lebanese intelligence services working in tandem, it would be difficult to envisage a scenario whereby such a complex assassination plot could have been carried out without their knowledge, and that there is probable cause to believe that the decision to assassinate former Prime Minister Rafiq Hariri could not have been taken without the approval of top ranked Syrian security officials,

Mindful of the Commission's conclusion that while the Syrian authorities, after initial hesitation, have cooperated to a limited degree with the Commission, several Syrian officials have tried to mislead the investigation by giving false or inaccurate statements,

Convinced that it is unacceptable in principle that anyone anywhere should escape accountability for an act of terrorism for any reason, including because of his own obstruction of the investigation or failure to cooperate in good faith,

Determining that this terrorist act and its implications constitute a threat to international peace and security,

Emphasizing the importance of peace and stability in the region, and the need for peaceful solutions,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

- I -

- 1. Welcomes the report of the Commission;
- 2. Takes note with extreme concern of the Commission's conclusion that, there is converging evidence pointing at the involvement of both Lebanese and Syrian officials in this terrorist act, and that it is difficult to envisage a scenario whereby such complex assassination could have been carried out without their knowledge;
- 3. Decides as a step to assist in the investigation of this crime and without prejudice to the ultimate judicial determination of the guilt or innocence of any individual;
- (a) that all individuals designated by the Commission or the Government of Lebanon as suspected of involvement in the planning, sponsoring, organizing or perpetrating of this terrorist act, upon notification of such designation to and agreement of the Committee established in subparagraph (b) below, shall be subject to the following measures:
- All States shall take the measures necessary to prevent entry into or transit through their territories of such individuals, provided that nothing in this paragraph shall obligate a state to refuse entry into its territory to its own nationals, or, if such individuals are found within their territory, shall ensure in accordance with applicable law that they are available for interview by the Commission if it so requests;
- All States shall: freeze all funds, financial assets and economic resources that are on their territories that are owned or controlled, directly or indirectly, by such individuals, or that are held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by such individuals or by persons acting on their behalf or at their direction; ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by their nationals or by any persons within their territories to or for the benefit of such individuals or entities; and cooperate fully in accordance with applicable law with any international investigations related to the assets or financial transactions of such individuals, entities or persons acting on their behalf, including through sharing of financial information;
- (b) to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council to undertake the tasks described in the annex to this resolution;
- (c) that the Committee and any measures still in force under subparagraph (a) will terminate when the Committee reports to the Security Council that all investigative and judicial proceedings relating to this terrorist attack have been completed, unless otherwise decided by the Security Council;
- 4. Determines that the involvement of any State in this terrorist act would constitute a serious violation by that State of its obligations to work to prevent and refrain from supporting terrorism, in accordance in particular with resolutions 1373 (2001) and 1566 (2004) and that it would amount also to a serious violation of its obligation to respect the sovereignty and political independence of Lebanon;

- 5. Takes note with extreme concern also of the Commission's conclusion that, while the Syrian authorities have cooperated in form but not in substance with the Commission, several Syrian officials tried to mislead the Commission by giving false or inaccurate information, and determines that Syria's continued lack of cooperation to the inquiry would constitute a serious violation of its obligations under relevant resolutions, including 1373 (2001), 1566 (2004) and 1595 (2005):
- 6. Takes note of the recent statement by Syria regarding its intention now to cooperate with the Commission and expects the Syrian Government to implement in full the commitments it is now making;

-11

- 7. Acknowledges that continued assistance from the Commission to Lebanon, as requested by its Government in its letter to the Secretary-General of 13 October 2005 and recommended by the Commission in its report, remains necessary to elucidate fully all aspects of this heinous crime, thus enabling that all those involved in the planning, sponsoring, organizing and perpetrating of this terrorist act, as well as their accomplices, be identified and brought to justice;
- 8. Welcomes in this regard the decision of the Secretary-General to extend the mandate of the Commission until 15 December 2005, as authorized by the Security Council in its resolution 1595 (2005), and decides that it will extend the mandate further if recommended by the Commission and requested by the Lebanese Government;
- 9. Commends the Lebanese authorities for the courageous decisions they have already taken in relation to the inquiry, including upon recommendation of the Commission, in particular the arrest and indictment of former Lebanese security officials suspected of involvement in this terrorist act, and encourages the Lebanese authorities to persist in their efforts with the same determination in order to get right to the bottom of this crime;

- III -

- 10. Endorses the Commission's conclusion that it is incumbent upon the Syrian authorities to clarify a considerable part of the questions which remain unresolved;
- 11. Decides in this context that:
- (a) Syria must detain those Syrian officials or individuals whom the Commission considers as suspected of involvement in the planning, sponsoring, organizing or perpetrating of this terrorist act, and make them fully available to the Commission;
- (b) the Commission shall have vis-à-vis Syria the same rights and authorities as mentioned in paragraph 3 of resolution 1595 (2005), and Syria must cooperate with the Commission fully and unconditionally on that basis;
- (c) the Commission shall have the authority to determine the location and modalities for interview of Syrian officials and individuals it deems relevant to the inquiry;
- 12. Insists that Syria not interfere in Lebanese domestic affairs, either directly or indirectly, refrain from any attempt aimed at destabilizing Lebanon, and respect scrupulously the sovereignty, territorial integrity, unity and political independence of this country;

- IV -

- 13. Requests the Commission to report to the Council on the progress of the inquiry by 15 December 2005, including on the cooperation received by the Commission from the Syrian authorities, or any time before that date if the Commission deems that such cooperation does not meet the requirements of this resolution, so that the Council, if necessary, could consider further action;
- 14. Expresses its readiness to consider any additional request for assistance from the Lebanese Government to ensure that all those responsible for this crime are held accountable;
- 15. Decides to remain seized of the matter.

Annex

The following are the functions of the Committee established pursuant to paragraph 3 of this resolution:

- 1. To register as subject to the measures in paragraph 3 (a) in this resolution an individual designated by the Commission or the Government of Lebanon, provided that within two working days of receipt of such designation no member of the Committee objects, in which case the Committee shall meet within fifteen days to determine the applicability of the measures in paragraph 3 (a).
- 2. To approve exceptions to the measures established in paragraph 3 (a) on a case-by-case basis:
- (i) with respect to the travel restrictions, where the Committee determines that such travel is justified on the ground of humanitarian need, including religious obligation, or where the Committee concludes that an exemption would otherwise further the objectives of this resolution;

- (ii) with respect to the freezing of funds and other economic resources, where the Committee determines that such exceptions are necessary for basic expenses, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or other financial assets or economic resources;
- 3. To register the removal of an individual from the scope of the measures in paragraph 3 (a) upon notification from the Commission or the Government of Lebanon that the individual is no longer suspected of involvement in this terrorist act, provided that within two working days of receipt of such designation no member of the Committee objects, in which case the Committee shall meet within fifteen days to determine the removal of an individual from the scope of the measures in paragraph 3 (a).
- 4. To inform all Member States as to which individuals are subject to the measures in paragraph 3 (a).

[F. No. U.II/152/31/2015]

RUDRENDRA TANDON, Jt. Secy. (UNP)